यूपी में निजी निवेशक बनाएंगे अस्पताल

अच्छी खबर 1

■ राजकुमार शर्मा

- निजी क्षेत्र की मदद से यूपी की सेहत सुधारने की तैयारी
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लाने जा रही नई नीति

लखनऊ। यूपी की की सेहत सुधारने के लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी। निजी निवेशक अस्पताल बनाएंगे और सरकार आर्थिक मदद के रूप में उन्हें ऑक्सीजन देगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य सरकार नई नीति लाने जा रही है। इसके जरिए स्वास्थ्य सेक्टर में निजी क्षेत्र के बड़े प्लेयरों को यूपी में अस्पतालों में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है।

देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य में सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना आसान नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में फिलवक्त न अस्पताल हैं और न ही डॉक्टर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के लिहाज से प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना जरूरी है। मगर उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा तकरीबन 19 हजार की आबादी पर एक चिकित्सक का है। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में यह सारा काम अकेले सरकार के वश का भी नहीं है। ऐसे में अब हेल्थ सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। खासतौर से प्रदेश में बड़े अस्पताल खोलने के लिए निजी निवेशकों की मदद ली जाएगी। इसके लिए नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है।

फीस तय करेगी सरकार, बदले में देगी आर्थिक मददः नई नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वालों को राज्य सरकार हर साल कुछ आर्थिक मदद देगी। अस्पताल निवेशक बनाएंगे। अस्पतालों पर स्वामित्व तो इसे बनाने वालों का ही रहेगा, मगर ओपीडी की फीस सहित इलाज की दरें राज्य सरकार तय करेगी। ताकि लोगों को उचित दरों पर इलाज मिल सके। तमाम प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज के नाम पर होने वाली लूट-खसोट को रोका जा सके। इसके एवज में अस्पताल के संचालन पर आने वाले खर्च में सरकार भी सहायता करेगी। इसके लिए बिडिंग सिस्टम अपनाया जाएगा। यानि निजी निवेशक अस्पताल संचालन के लिए राज्य सरकार से सालाना कितनी धनराशि चाहते हैं, इसकी बिड (निविदा) डाली जाएगी। जिनका प्रस्ताव कम धनराशि का होगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।